Diesel Power Stations

7003. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether a number of State Electricity Boards have invited tenders/ signed MOUs with IPPS for 100 MW Diesel Power Stations; if so, the details thereof:

(b) whether the fuel for the above projects would be either furnance oil or low sulphur heavy stock;

(c) what would be the requirements of fuel at the plant load factor guaranteed by the IPPS on implementation of the projects;

(d) whether the above proposals have already been approved by CEA/ Ministry of Petroleum and Natural Gas/the Oil Coordination Committee; and

(e) whether there will be a dual price for diesel for agricultural sector, which is subsidised and for power sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) Some of the State Electricity Boards have invited offers from the private promoters for setting up of power plants based on liquid fuel.

(c) to (e) Fuel policy for the power sector operation parameters for liquid fuel based power projects is at present under consideration of the Government of India. A view on the proposals could be taken only after Government finalises its policy.

हिमालय में नदी प्रपातों से पन-बिजली उत्पन्न किया जाना

7004. श्री रामजी लाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के विभिन्न नदी प्रपातों को जोड़कर एक राष्ट्रीय पूल बनाएगी, यदि हां, तो इस पूल की पन-बिजली के उत्पादन की क्षमता क्या होगी ;

(ख) क्या हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली मुख्य नदियों पर ऐसे प्रपातों का पता लगाना अभी बाकी है ;

(ग) यदि हां, तो इन सभी प्रपातों का उपयोग करके देश में कितनी पन-बिजली उत्पन्न किए जाने की संभावना है तथा इसके परिणामस्वरूप देश को कितने प्रतिशत बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी ;

(घ) ऐसी परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का अनुमान है ; और

(ङ) सरकार इसका प्रावधान कैसे करेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) से (ङ) इस समय देश में विभिन्न प्रपातों को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय पूल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय संदर्शी योजना से संबंधित अध्ययन कार्य कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भंडारों के निर्माण और देश की कुछ नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में दो घटक हैं यथा, हिमालय घटक और प्रायद्वीपीय घटक। यह अनुमान लगाया गया है कि हिमालय घटक में अभिज्ञात परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों में लगभग 30 मिलियन किलो वाट विद्युत का उत्पादन और प्रायद्वीपीय घटक में लगभग मिलियन किलोवाट विद्युत का उत्पादन शामिल है।

के० वि० प्रा० द्वारा देश में वर्ष 1987 में जल विद्युत शक्यता के बारे में पूरे किए गए पुनर्मूल्यांकन के अनुसार देश में उपलब्ध कुल जल विद्युत शक्यता का 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 84044 मे० वा० का अनुमान लगाया गया है। इसमें से तीन नदी बेसिनों की जल विद्युत शक्यता का जो हिमालय क्षेत्र में तथा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आते हैं, 65,623 मे० वा० (60